अगर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे।
– अज्ञात

राजनीति में क्या–कुछ घट रहा

व्लादिमीर पूतिन की स्थिति रूस के बेताज बादशाह जैसी है, हालांकि वह रूसियों को बड़ी कुशलता के साथ यह आभास दिलाते रहे हैं कि वे एक लोकतंत्र में रहते हैं और उनके पास भी वे तमाम अधिकार हैं जो बाकी लोकतांत्रिक देशों में हुआ करते हैं।

रेखा वर्मा।

रूस की चर्चा आमतौर पर वैश्विक कूटनीति के संदर्भ में ही होती है। वहां की आंतरिक राजनीति में क्या–कुछ घट रहा है, इसकी खबरें कम आती हैं। बहरहाल, हाल में वहां से आए एक समाचार ने सबको चौंका दिया। समाचार यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन के देश में व्यापक संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखने के बाद प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। मेदवेदेव ने कहा कि राष्ट्रपति पूतिन के इन प्रस्तावों से देश के सत्ता ढांचे और शक्ति संतुलन में काफी अहम बदलाव आएंगे। पूतिन ने जो प्रस्ताव रखे हैं उन्हें लेकर देश भर में वोटिंग कराई जाएगी। इनके लागू होने की स्थिति में सत्ता की ताकत राष्ट्रपति से ज्यादा संसद के पास होगी। ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि

पूतिन ने यह कदम खुद को 2024 के बाद भी सत्ता के शीर्ष पर बनाए रखने के लिए उठाया है। प्रेजिडेंट के रूप में उनका चौथा कार्यकाल 2024 में खत्म होने जा रहा है और मौजूदा संविधान के तहत वह अगली बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते। व्लादिमीर पूतिन की स्थिति रूस के बेताज बादशाह जैसी है, हालांकि वह रूसियों को बड़ी कुशलता के साथ यह आभास दिलाते रहे हैं कि वे एक लोकतंत्र में रहते हैं और उनके पास भी वे तमाम अधिकार हैं जो बाकी लोकतांत्रिक देशों में हुआ करते हैं। आगे भी सत्ता में बने रहने के लिए वे एक नई प्रणाली लाने का नाटक कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उनके ऊपर न तो जनता का कोई दबाव है, न ही विपक्ष का।

कह सकते हैं कि रूस में 'पूतिन मार्का जनतंत्र' चल रहा है। लेकिन यह रातोंरात नहीं हो गया। पूतिन ने बड़े सुनियोजित तरीके से अपनी ताकत बढ़ाई। पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने अस्वस्थ होने की वजह से 31 दिसंबर 1999 को जब अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, तब पूतिन ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली थी। फिर मार्च 2000 में जनता ने राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें चुन लिया। सत्ता में आने के कुछ दिन बाद ही पूतिन ने मीडिया पर नियंत्रण कायम करना शुरू कर दिया। मीडिया मुगल कहलाने वाले गुसिन्स्की के स्वतंत्र चौनल एनटीवी जैसे बड़े संस्थानों को विवश किया गया कि वे सारे कार्यक्रम सरकार के पक्ष में ही दिखाएं।

पूतिन की पॉपुलैरिटी रेटिंग को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाएं और उनके विरोधियों पर उंगली उठाएं। उसके बाद पूतिन ने उन कुलीनों को निशाना बनाया जो रूस की राजनीति में खासा दखल रखते थे। उनमें से कुछ को जेल में डाल दिया गया और कुछ देश छोड़ने को मजबूर हो गए। पूतिन ने राष्ट्रवाद, सेना और धर्म को बढ़ावा देते हुए 'महान रूस' की छवि बनाने की कोशिश की, साथ ही प्रॉक्सी अपोजिशन भी खड़ा किया। उन्होंने बाकी विपक्ष दलों से भी कामचलाऊ रिश्ते बनाए रखे। देखें, इस नए दांव से वह अपनी सत्ता को कितना आगे ले जाते हैं।

सनातन संस्कृति

डॉ. अर्चिका दीदी।

धर्म-दर्शन

हे सनातन संस्कृति के सपूतो! ऐसे लोगों को अनीश्वरवादी कहो या अपना अहंकार सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जानेवाले तमस्–प्रधान प्रकृति के कूटनीतिज्ञ लोग कहो, उनके विरुद्ध लोहा लेने के लिए अब हम सभीको तैयार रहना पड़ेगा। ओम्... ओम्... ओम्... जुल्म करना तो पाप है, पर जुल्म सहना दुगना पाप है। अब हमें उद्यम करना होगा, अपनी संस्कृति की रक्षा एवं सेवा के लिए हमें साहसी बनना होगा। धैर्यवान होकर, आगे–पीछे का गणित लगाकर हमें कदम आगे रखने होंगे। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम – ये छरू सद्गुण तो हमारे अपने घर का खजाना है। अब उस खजाने को खोलना है।

संपादकीय

ब्याज के बंधन खोलेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने एक ऐसा बजट पेश करने की चुनौती है जो हर तबके के लोगों को राहत दे। उनके पास संसाधन कम हैं, टैक्स वसूली लक्ष्य से कम है और खर्चे लंबे–चौड़े हैं। लोगों को उनसे उम्मीदें बहुत हैं और मिडल क्लास को हमेशा की तरह इनकम टैक्स में कटौती का इंतजार है, लेकिन सरकार के खजाने में उतना धन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जीडीपी विकास की दर लगातार गिरती जा रही है और निवेश नहीं हो पा रहा है।

2019 में जीएसटी वसूली का औसत प्रति माह एक लाख करोड़ रुपये से भी कम रहा। इससे सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं और उसने विभाग पर जोर डाला है कि रेवेन्यू का लक्ष्य वह बचे हुए महीनों में पूरा कर ले। स्थितियों को देखते हुए वित्त मंत्री के सामने सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के अलावा आमदनी का कोई बड़ा रास्ता नहीं रह जाएगा। सरकारी कंपनियों के शेयर बेचकर सरकार कुछ राजस्व इकट्ठा कर लेगी और इसके बल पर राजस्व घाटे को लक्ष्य के करीब रखने का प्रयास करेगी। एयर इंडिया को बेचने की तैयारी तो हो चुकी है, एमएमटीसी, एनएमडीसी, मेकॉन और बीएचईएल के शेयर भी उसे 31 मार्च तक बेच ही देने होंगे ताकि चालू बजट के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। पिछले बजट में सरकार ने कुल बजट राशि का 3.3 प्रतिशत राजस्व घाटे का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह न सिर्फ पूरा हो चुका है बल्कि उससे आगे बढ़ चुका है। सीमा रेखा का पालन करना वित्त मंत्री के लिए बहुत कठिन है। बजट के विभिन्न मदों में जितनी राशि का आवंटन करना है और जो टैक्स वसूली तथा अन्य प्राप्तियां होनी हैं, उसके बाद बजट घाटे की परवाह करना संभव नहीं होगा। बहरहाल, वित्त मंत्री को इस बारे में चिंता करनी चाहिए या नहीं, यह भी एक बहस का विषय है।

इधर भी अंतिम रूप से प्रत्याशी का नाम तय होने में अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन शुरुआती चरण में जिन दो नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है, वे हैं कमला हैरिस और तुलसी गबार्ड।

नारी वस्त्र पहनते थे एनटीआर

केसी त्यागी।

1984 को देश की राजनीति का उथल–पुथल का वर्ष माना जाता है। विश्व बैंक से इस्तीफा देकर किसान राजनीति में शामिल हुए शरद जोशी महाराष्ट्र किसानों के बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। चौधरी चरण सिंह के साथ मैं और पूर्व सांसद अजय सिंह, शरद पवार के निमंत्रण पर अहमद नगर में आयोजित किसान रैली में शामिल हुए। इस रैली का पूरा प्रबंधन शरद पवार द्वारा किया जा रहा था। रैली में कई लाख की भीड़ एकत्र हुई थी। सभी ने आह्वान किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मतदान किया जाए। हमारे मुंबई पहुंचते तक देश की राजनीति अपने उबाल पर आ चुकी थी।

तेलुगु फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता और मुख्यमंत्री एनटी रामाराव अपने दिल के ऑपरेशन के लिए अमेरिका में थे, वहीं उन्हें तख्ता पलट होने का संदेश मिला। उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक सहयोगी एन. भास्कर राव ने अपने को टीडीपी का असली नेता बताते हुए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। हिमाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रामलाल उस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। हिमाचल में भ्रष्टाचार में कई मामले में उनकी संलिप्तता साबित हो चुकी थी। उन्होंने एन. भास्कर राव को बगैर संख्या बल की परीक्षा

किए ही आनन–फानन शपथ दिला दी। इस घटनाक्रम ने समूचे विपक्ष को एकजुट कर दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए आंध्र प्रदेश सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 1977 के आम चुनाव में जब श्रीमती गांधी स्वयं चुनाव हार गई थीं, उस समय भी कांग्रेस पार्टी को आंध्र प्रदेश में 42 में से 41 सीटें मिली थीं और बाद में वह एक उपचुनाव में स्वयं भी वहीं की मेडक लोकसभा सीट से निर्वाचित हुई थीं। इंदिरा गांधी के शासन काल में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अदला–बदली का दौर निरंतर बना रहता था। ऐसे ही एक अपमानजनक घटनाक्रम में वहां के मुख्यमंत्री टी. अन्जैया को हटाया गया जिससे तेलुगु स्वाभिमान हिल गया।

उसी दौर में एनटी रामाराव ने राजनीति में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। तेलुगु स्वाभिमान के नाम पर उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद एनटी रामाराव ने इस अस्मिता को एक बार फिर से जगाया। एक रथ में सवार होकर समूचे प्रदेश में जनजागरण के लिए निकल पड़े। इसी बीच विपक्षी एकता के प्रयास भी तेज हो रहे थे। लोकसभा चुनाव में 6 महीने ही रह गए थे। एनटी रामाराव स्वयं भी राष्ट्रीय राजनीति में आने के संकेत देने लगे जब उन्होंने दिल्ली आकर सभी शीर्ष नेताओं से मिलना–जुलना शुरू कर दिया।

अपने हैदराबाद स्थित बंजारा हिल्स आवास में हिंदी के दो अध्यापकों की नियुक्ति भी की। उन दिनों एक आम चर्चा थी कि किसी ज्योतिषी के कहने पर प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा से वह रात्रि में नारी वस्त्र भी धारण करने लगे थे। चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली लौटकर विपक्षी एकता के प्रयास तेज कर दिए। पार्टी कार्यालय में बड़े विपक्षी नेताओं के जमावड़े लगने शुरू हो गए जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, चंद्रशेखर, ईएमएस नंबूदिरीपाद, सी राजशेखर राव, शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला और मेनका गांधी समेत कई नेता उपस्थित रहते थे।

सूडोकु नवताल- 5223

✱✲✲✲✲ सरल

			2				3	
		9		8		2	6	4
1				3	6		9	
4		3						
	8			2			1	
						8		6
	4		7	5				3
3	7	5		4		1		
	2				8			

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5222 का हल

8	4	5	6	1	3	7	2	9
7	2	6	4	9	5	3	8	1
9	3	1	7	8	2	6	5	4
1	7	2	9	6	8	4	3	5
5	6	9	3	2	4	1	7	8
4	8	3	5	7	1	9	6	2
2	9	7	1	5	6	8	4	3
3	1	8	2	4	7	5	9	6
6	5	4	8	3	9	2	1	7

अपना ब्लॉग

इकॉनमी डेफिसिट फाइनेंसिंग से चलती है

मुकुल श्रीवास्तव। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि हमारी इकॉनमी डेफिसिट फाइनेंसिंग से चलती है, यानी सरकार जरूरत के हिसाब से नोट छाप लेती है। उनकी राय है कि राजस्व घाटे के लक्ष्य की परवाह नहीं करते हुए खर्च बढ़ाया जाए। मनमोहन सिंह सरकार के पांचवें साल में यह 4.5 प्रतिशत तक चला गया था। उस हिसाब से मोदी सरकार ने अब तक राजस्व घाटे के अपने लक्ष्य को बरकरार रखा है। समय आ गया है कि वह इस बारे में थोड़ी ढिलाई बरते और खर्च के लिए बड़ी राशि निकाले। मुद्रास्फीति काबू में रहती तो यह रास्ता अपनाया जा सकता था, लेकिन इधर वह भी काबू से बाहर होती जा रही है। थोक वस्तुओं के भाव में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन खुदरा मुद्रास्फीति जो नवंबर में 5.5 प्रतिशत थी, वह दिसंबर में बढ़कर 5 साल में अधिकतम यानी 7.35 फीसदी हो गई है, जो आरबीआई के आकलन से ज्यादा है।